THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) and (b) Government have seen the news-item but no specific mention was made by Director General, B S F. about involvement of six families in smuggling activities on Punjab border and their assets and properties. What Director General B.S.F. had stated was that the entire smuggling operations were organised by a handful of persons.

(c) The Customs field formations on the Indo-Pak border remain vigilant. The preventive and Intelligence machinery of the Custums Department in the region has been reinforced in terms of manpower and equipment. In addition, appropriate antismuggling measures are taken in close co-ordination with the concerned Central and State Government authorties. The matter is kept under constant review for appropriate action.

Funds for Development of Tribal Areas

4786. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether the Eighth Finance Commission has recommended funds for the development of tribal areas and socio-economic upliftment of the tribals under the first proviso to Article 275 of the Constitution;

(b) if so, the total funds suggested for tribal areas and distributed to the concerned States;

(c) whether this fund will flow from consolidated fund of India or from Government's Budget Funds; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF FINANCE(SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Under the terms of reference for the 8th Finance Commission, the Commission was required to make recommendations as to the principle which should govern the grants-in-aid of revenues of the States out of the consolidated fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grant-in-aid of their revenue under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article. The Ministry of Home Affairs have made the following provisions under Demand No. 55 in their Budget for 1984-85 for the purposes mentioned in the provisos to the Article 275.

D.2(1)—Grants under provisos to article 275(1) of the Constitution.

D.2(1) (I)—Schemes under provisos to Article 275(1) of the Constitution (Charged Rs. 20 crores.

D.1(1)(1) Grants to Assam Government Under clause (a) of the second proviso to article 275(1) of the Constitution (Charged) Rs. 13.33 lakhs.

The Finance Commission provided grants for upgradation of Tribal administration and Article 275 (2) of the Constitution. The Commission had recommended a total grant of Rs. 27.19 crores for the five years period 1984-85 to 1988-89 for upgradation of standards of tribal administration in the States. The Government have accepted the recommendations of the Commission for four years commencing from 1st day of April, 1985. The relatable grant for this period would be Rs. 81 318 crores.

(c) The funds mentions above will be charged on the Consolidated Fund of India.

(d) Does not arise.

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 'मार्जिन' राशि के आबंटन हेतु अपनाया गया मान दण्ड

4787. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए 'मार्जिन' राशि के आबंटन में क्या मानदन्ड अपनाया है;

(ख) क्या अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी को उक्त मानदण्ड में शामिल नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मानदन्ड के अनुसार धन-राशि का राज्यवार कितना आबंटन किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आठवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए सीमांत राशि (मार्जिन मनी) 1982-83 को समाप्त हुए पांच वर्षों में औसत आयोजना भिन्न व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की है। इस प्रकार परिकलित की गई सीमांत राशि को सातवें आयोग द्वारा निर्धारित सीमांत राशि के तीन गुना तक सीमित रखा गया है और इस राशि को अगले 25 लाख रुपए की राशि तक पूर्णांकित किया गया है। कुछ राज्यों के संबध में जहां आठवें वित्त आयोग द्वारा 5 वर्ष के औसत के आधार पर परिकलित सीमांत राशि सातवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि से भी कम बैठती थी, आठवें वित्त आयोग द्वारा आबटित राशि जितनी राशि की व्यवस्था की है। इस प्रकार निर्धारित की गई सीमांत राशि के आधे भाग को राज्यों के राजस्व के पूर्वानुमानों का पुनर्निर्धारण करते हुए हिसाब में लिया गया है और शेष आधी राशि केन्द्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत सहायता अनुदानों के रूप में दी जाएगी।

(ख) अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को दी जानी वाली मजदूरी की सीमांत राशि में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह सामान्यतः आयोजना-व्यय में शामिल होती है। इस सम्बन्ध में आठवां वित्त आयोग सातवें वित्त आयोग के विचारों से सहमत था, जो इस प्रकार है :—

> "हमने जिस मार्जित की व्यवस्था की है उसमें किसी वर्ष में अधिक किए गए व्यय के लिए .....राज्य सरकार को अपनी आयोजना से अधिकांशतः सूखे के प्रभाव का निराकरण करने के हेतु राहत सम्बन्धी रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अपनी आयोजना से अंशदान देना चाहिए..... इस संबंध में हम समझते हैं कि नई पचवर्षीय आयोजना में सूखे की सभावना से ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रमों, और अन्य विकास कार्यक्रमों तथा साथ ही न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे सड़कों, पेयजल आदि के लिए काफी अधिक परिव्यय की सम्भावना है और इसमें से राहत संबंधी रोजगार के प्रयोजनों के लिए राशि ली जा सकती है। हम आशा करते हैं कि योजना आयोग और राज्य सरकारें भी विपदा के समाप्त हो जाने के बाद राहत प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किए गए निर्माण कार्यों की सम्पन्नता को आयोजना में महत्व देगी।"

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, सातवें वित्त आयोग का यह मत था कि सीमांत राशि में राहत-रोजगार संबंधी व्यय को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आठवें वित्त आयोग ने सातवें वित्त आयोग के विचारों से सहमति प्रकट की थी।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित की गई वार्षिक सीमांत राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

1. आंध्र प्रदेश	24.50
2. आसाम	7.25
3. बिहार	33.75
4. गुजरात	28.75
5. हरियाणा	4.50
6. हिमाचल प्रदेश	1.75
7. जम्मू और कश्मीर	1.50
8. कर्नाटक	6.00
9. केरल	5.00
10. मध्य प्रदेश	4.75
11. महाराष्ट्र	7.25
12. मणिपुर	0.25
13. मेघालय	0.25
14. नागालैण्ड	0.25
15. उड़ीसा	26.25
16. पजाब	5.00
17. राजस्थान	16.75
18. सिक्कम	0.25
19. तमिलनाडु	8.75
20. त्रिपुरा	0.75
21. उत्तर प्रदेश	32.50
22. पश्चिम बगाल	23 75
जोड़	240.75

Gold declared by temples of Tamil Nadu under gold control act

4788. SHRI ERA MOHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the quantum and value of gold and gold ornaments which have been declared under the Gold Control Act by thc temples in Tamil Nadu;

(b) whether there is any machinery to check regularly the quantum of gold in different temples in Tamil Nadu; and

(c) if so, whether any thefts and pilferage have come to the notice of Government and the action taken thereon?

THE MINISTER OF SATAE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) Under section 16 of the Gold (Control) Act, 1968, a religious institution has to declare only the quantity of gold, gold articles and ornaments in its possession to the jurisdictional Gold Control Officer. A quantity of 3144 Kgs. of gold in all forms was declared as on 31.12.1983 by religious institutions in Tamil Nadu including Union Territory of Pondicherry.

(b) and (c) The gold declared is the property of the temples. The temples of Tamil Nadu are under the control of the Hindu Religious and Charitable Endowments Board of the State Government of Tamil Nadu. The verification etc. of the property (including gold) belonging to the temples is being done periodically by the officers of the State Government. It is the responsibility of the State Government to take appropriate action against the thefts, pilferage, etc.

कड़ी स्थित नवज्योति कपड़ा मिल का पुन: चालू किया जाना

4789. श्री मोती भाई आर. चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :